

दि कर्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 9

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 18 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023

पेज : ८

कीमत : 3 रुपये

भारत की जी20 अध्यक्षता में पहला पी20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मेजबानी में आयोजित पहला जी20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन (पी20 शिखर सम्मेलन) आज 14 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, यशोभूमि में संपन्न हो गया। दुनियाभर के संसद सदस्य यहां एक साथ बैठे और जी20 प्रक्रिया में प्रभावी एवं सार्थक संसदीय योगदान के लिए अपने संयुक्त कार्यों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। 9वें पी20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 13 अक्टूबर, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था और आज लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आखिर में समापन भाषण दिया। समापन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्टो पाचेको, जी20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन से पहले 12 अक्टूबर, 2023 को मिशन लाइफ पर संसदीय फोरम की बैठक हुई थी।

समापन सत्र में आज साथी सांसदों और अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने एक पृथ्वी,



एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसदों% विषय पर पी20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान के लिए जी20 और आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों को धन्यवाद दिया। श्री बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संयुक्त वक्तव्य को अपनाने में पी20 प्रक्रिया और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि एसडीजी, हरित ऊर्जा, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना- इन चारों विषयों पर आयोजित सत्रों में आपने बहुमूल्य सुझाव और अपने अनुभव साझा किए हैं। मुझे विश्वास है कि यह मानव-केंद्रित विकास के लिए जी20 प्रक्रिया को और मजबूत करेगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दो दिनों के दौरान हुए विचार-विमर्श ने जी20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और यह स्थापित भी किया है कि किस प्रकार एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी संसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुपक्षवाद पर जोर देते हुए श्री बिरला ने कहा कि आज आपस में जुड़ी दुनिया में हम किसी विशेष मुद्दे को अलग नहीं देख सकते हैं। उन्होंने संयुक्त वक्तव्य के पैराग्राफ 27 को दोहराया जो इस प्रकार है- हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतरराष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनयिक और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। श्री बिरला ने आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और सारी

प्रतिबद्धताओं को पी20, जी20 और उससे भी आगे बढ़ाने के संकल्प को दोहराया। संसद सदस्यों की भूमिका पर बोलते हुए अध्यक्ष ने कहा कि हम इस स्थिति में हैं कि जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी नीतियां और कानून का निर्माण कर सकें। हमारी भूमिका सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में तथा जन कल्याण के उद्देश्य से सुशासन सुनिश्चित करने में हमारी संसदों और संसद सदस्यों का विशेष योगदान है। भारत की पी20 प्रेसीडेंसी समाप्त होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने ब्राजील की संसद को अध्यक्षता सौंप दी। भारत और आईपीयू का साझा लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय शासन संरचनाओं का लोकतंत्रीकरण करना है जो मौजूदा वास्तविकताओं को प्रदर्शित करता है- लोकसभा अध्यक्ष, आईपीयू अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता में पी20 शिखर सम्मेलन से इतर लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष डुआर्टो पाचेको से मुलाकात की।

गोपाल राय ने केंद्र से की पटाखों पर बैन लगाने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। ऐसे में दिवाली पर आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का लेवल और बढ़ जाता है। इसको लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार से पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा कि दिल्ली सरकार ने सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन, ये तब तक प्रभावी साबित नहीं होंगे जब तक हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एनसीआर में प्रदूषण के स्रोतों से खत्म नहीं होंगे।

गोपाल राय ने कहा कि पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट' की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में केवल 31 ब प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी के स्रोतों से होता है। वहीं 69 प्रतिशत प्रदूषण एनसीआर से आता है। इसको लेकर गोपाल राय ने

केंद्र सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों से निपटने पर चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाई जाए। गोपाल राय ने कहा कि एनसीआर में आने वाले राज्यों को पूरे क्षेत्र में पटाखों और पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। वहीं दिल्ली में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन की अनुमति देनी चाहिए। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि एनसीआर के तहत आने वाले राज्यों में अब भी कई ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं, प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हें तुरंत पाइपड प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया जाना चाहिए। एनसीआर राज्यों में संचालित भारी प्रदूषण फैलाने वाले ईट भट्टों को प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जिग-जैग तकनीक अपनाने के लिए कहा जाना चाहिए। राय ने पत्र में लिखा है कि डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम करते हुए एनसीआर राज्यों में सभी हाउसिंग सोसायटियों में बिजली सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नई दिल्ली। भारत सहित पूरी दुनिया के लगभग 80 प्रतिशत किसान धान की पराली जलाते हैं, जिससे गंभीर वायु प्रदूषण फैलता है। जो हर साल घनी आबादी और ज्यादा औद्योगिक घनत्व वाले भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अक्टूबर-नवंबर महीने में हवा की गति कम होने और हिमालय से ठंडी हवा आने से बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस वायु प्रदूषण समस्या के समाधान के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्चने के बाद भी विफल रही हैं।

देश में सबसे ज्यादा उपजाऊ और सिंचित उत्तर पश्चिम भारतीय मैदानी क्षेत्र में हरित क्रांति के दौर में (1967-1975) राष्ट्रीय नीतिकारों द्वारा प्रायोजित धान-गेहूं फसल चक्र ने पिछले पांच दशकों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और लगभग एक लाख करोड़ रुपए वार्षिक निर्यात को तो सुनिश्चित किया, लेकिन गंभीर भूजल बर्बादी, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या को बढ़ाया। सरकार द्वारा फसल विविधकरण के सभी प्रयासों के बावजूद धान-गेहूं फसल चक्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि पर अपनाया जा रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मौसम अनुकूलता और आर्थिक तौर पर गन्ने की खेती के अलावा धान - गेहूं फसल चक्र ही किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। (स्रोत: कृषि लागत एवं मूल्य आयोग-गन्ने की मूल्य नीति- चीनी मौसम -2023-24 रिपोर्ट, पेज -76). उत्तर पश्चिम भारत के प्रदेशों में धान-गेहूं फसल चक्र में लगभग 40 क्विंटल फसल अवशेष प्रति एकड़ पैदा होते हैं, जिसमें से आधे फसल अवशेष 20

क्या है पर्यावरण हितैषी स्थायी समाधान?

क्विंटल प्रति एकड़ यानि गेहूं के भूसे का प्रबंधन किसानों के लिए कोई खास समस्या नहीं है, क्योंकि पशु चारे के रूप में गेहूं का भूसा फायदेमंद होने और अगली फसल की बुआई की तैयारी में काफी समय (50-60 दिन) मिलने के कारण, किसान गेहूं भूसे का प्रबंधन आसानी से कर लेते हैं। लेकिन बाकि बचे आधे फसल अवशेष यानि धान पराली का प्रबंधन किसानों के लिए वर्षों से गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि धान की पराली आमतौर पर पशु चारे के लिए उपयोगी नहीं होने और अगली फसल की बुआई की तैयारी में मात्र 20 दिन से कम समय मिलने के कारण, धान की कटाई के बाद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बड़ी मात्रा में किसान पराली जलाते हैं। इससे अक्टूबर-नवंबर महीने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित जम्मू से कोलकता तक के बहुत बड़े क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा होती है, जिस के कारण, पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचता ही है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है।

पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश सरकारों/वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, किसानों पर जूरमाना लगाने, बायो-डीकंपोजर से पराली गलाने, जैसे अव्यावहारिक प्रयास कर रही

हैं। जिनके अभी तक कोई सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। पूसा डीकंपोजर के प्रायोजक पूसा संस्थान का मानना है कि डीकंपोजर घोल के छिड़काव से 25 दिन बाद पराली कुछ नरम तो होती है, लेकिन इसे पूर्णतया गलाने के लिए सात सप्ताह (50 दिन) का समय चाहिए और बायो- डीकंपोजर कभी भी मशीनीकरण द्वारा पराली प्रबंधन का विकल्प नहीं बन सकता है। वहीं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अनुसंधान बताते हैं कि बायो- डीकंपोजर छिड़काव से कोई खास लाभ नहीं होता, जबकि धान कटाई के बाद गहरी जुताई द्वारा पराली को भूमि में दबाने और खेत में समुचित नमी बनाए रखने से, बिना बायो-डीकंपोजर छिड़काव भी पराली 7 सप्ताह में ही गल जाती है। (अंतरराष्ट्रीय जर्नल ऑफ रिसाईक्लिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, 13 नवम्बर 2022 संस्करण)। धान पराली व फसल अवशेष प्रबंधन पर सभी अनुसंधान और तकनीकी रिपोर्ट इस बात पर एकमत हैं कि मशीनीकरण द्वारा फसल अवशेषों को खेत से बाहर निकाल कर उद्योगों आदि में उपयोग करना इसका सर्वोत्तम समाधान है। जैसा कि अमेरिका आदि देशों में वर्षों से हो रहा है। लेकिन भारत में भूमि की छोटी जोत होने से किसानों के लिए भारी मशीन खरीदना सम्भव नहीं है। ऐसी हालत में धान कटाई के बाद पराली को भूमि में मिलना ही व्यावहारिक समाधान बनता है। लेकिन यह तभी

सम्भव हो सकेगा, जब पराली को भूमि के अन्दर दबाने और गलाने के लिए 45-50 दिन समय मिलेगा। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों और राष्ट्रीय नीतिकारों को उत्तर पश्चिम भारत के लिए, धान की खेती के लिए किसान और पर्यावरण हितैषी नयी तकनीक और बुआई कलेंडर आदि विकसित करने होंगे। पराली प्रदूषण और भूजल बर्बादी रोकने के लिए धान की सीधी बिजाई पद्धति में कम अवधि वाली किस्में एक सस्ता और कारगर उपाय है। धान फसल की कटाई और रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों, आलू आदि की बुआई की तैयारी में कम समय मिलने के कारण ही किसान मजबूरन धान पराली जलाते हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय नीतिकारों को पराली प्रदूषण और भूजल बर्बादी रोकने के लिए धान की सीधी बिजाई पद्धति में कम अवधि वाली धान किस्मों (जैसे पी.आर.-126, पी. बी.-1509 आदि) को प्रोत्साहन एक कारगर उपाय साबित होगा और लम्बी अवधि की किस्मों पूसा-44 आदि पर कानूनी प्रतिबंध जरूरी है। इसमें धान फसल की बुआई 20 मई से शुरू हो कर, फसल की कटाई 30 सितम्बर तक पूरी हो जाती है। उल्लेखनीय है कि रोपाई पद्धति के मुकाबले सीधी बिजाई में धान की सभी किस्में 10 दिन जल्दी पक कर तैयार हो जाती है, जिस कारण गेहूं फसल बुआई से पहले किसान को लगभग 45-50 दिन का समय धान पराली व

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मिलता है। इसका सदुपयोग करके, किसान गेहूं - धान फसल चक्र में हरी खाद के लिए ढेंचा, मूंग आदि फसल भी उगा सकते हैं, जिससे पराली जलाने से पैदा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी, भूमि की ऊर्वरा शक्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी और रसायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार इन प्रदेशों में अगर धान की सरकारी खरीद की समय सारणी 15 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक का समय निश्चित करे, तो किसान स्वयं धान की सीधी बिजाई पद्धति में कम अवधि वाली धान किस्मों को ही अपनाएंगे, इससे लगभग एक तिहाई भूजल, ऊर्जा (बिजली- डीजल- मजदूरी) और खेती लागत में बचत के साथ पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। इन प्रदेशों में लगभग 90 प्रतिशत धान की कटाई व गहाई कंबाईन हारवेस्टर मशीनों द्वारा किराये पर होती है। सरकार कानून बनाकर, पराली को भूमि में दबाने की जिम्मेवारी भी कंबाईन हारवेस्टर मालिक की निश्चित करे। इस वर्ष खरीफ 2023 सीजन में, हरियाणा सरकार द्वारा धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहन योजना के सकारात्मक नतीजे के कारण, प्रदेश के किसानों ने तीन लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर धान की सीधी बिजाई विधि को अपनाया। जिसके परिणाम स्वरूप 30 सितम्बर 2023 तक प्रदेश की मंडीयों में आठ लाख टन धान बिकने के लिए आया। जो पर्यावरण हितैषी धान की सीधी बिजाई विधि में किसानों के विश्वास को दर्शाता है।

दुनिया के कई देशों में सूखे से बिगड़े हालात

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने गुरुवार को आगाह किया है, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते इंसानी हस्तक्षेप के कारण धरती पर मौजूद जल संसाधन बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं, इसकी वजह से पृथ्वी का जल चक्र तेजी से गड़बड़ा रहा है। इसका स्वामि राजा किसी और को नहीं हम इंसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। यह जानकारी डब्ल्यूएमओ द्वारा जारी नई रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2022' में सामने आई है। रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए गए हैं वो जल संकट को लेकर गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आज वैश्विक स्तर पर करीब 360 करोड़ लोग साल में कम से एक महीने जल संकट का सामना करने को मजबूर हैं। वहीं आशंका है कि यह आंकड़ा अगले 27 वर्षों में बढ़कर 500 करोड़ पर पहुंच जाएगा। देखा जाए तो भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में जल संकट की स्थिति पहले ही काफी गंभीर हो गई है। एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ भारी बारिश, जलवायु से जुड़ी ये चरम मौसमी घटनाएं आज जनजीवन और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। इतना ही नहीं हिमालय, आल्प्स जैसे पहाड़ों पर पिघलती बर्फ और घटते ग्लेशियरों ने बाढ़ जैसी आपदाओं के खतरों को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी वजह से लाखों लोगों के लिए उपलब्ध जल संसाधन धीरे-धीरे घटता जा रहा है। नतीजन भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने अपनी इस रिपोर्ट के लिए उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों, जमीनी सर्वे, मॉडलिंग और रिमोट सेंसिंग जैसे तकनीकों की मदद ली है। इसमें जल संबंधित प्रमुख कारकों, जैसे भूजल, भूमिगत प्रवाह, वाष्पीकरण, नदियों के प्रवाह, मिट्टी में मौजूद नमी, जमे हुए जल स्रोत (क्रायोस्फीयर), जलाशय उनके प्रवाह, सतह पर मौजूद जल भंडार और जल संबंधित आपदाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के बारे में डब्ल्यूएमओ के महासचिव प्रोफेसर पेटेरी तालास का कहना है कि, यह रिपोर्ट दुनिया भर में जल संसाधनों का एक व्यापक और सुसंगत आकलन प्रस्तुत करती करती है, जिसमें जल संसाधनों पर जलवायु, पर्यावरणीय और सामाजिक बदलावों के पड़ने वाले प्रभावों को उजागर किया गया है। उनका आगे कहना है कि, ग्लेशियर और बर्फ के आवरण हमारी नजरों के सामने ही घट रहे हैं। बढ़ता तापमान ने केवल जल चक्र को तेज बल्कि बाधित भी कर रहा है। गर्म वातावरण में अतिरिक्त नमी होती है, जिससे भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ, बढ़ते वाष्पीकरण से मिट्टी शुष्क हो रही है गंभीर सूखे की स्थितियां बन रही हैं। 2022 में दुनिया के आधे से अधिक जलाशयों और जलग्रहण क्षेत्रों में स्थिति सामान्य से अलग थी। नदियों का प्रवाह भी उम्मीद से अलग था। अधिकांश जलाशय और जलग्रहण क्षेत्र सामान्य से अधिक शुष्क थे, जैसा कि 2021 में भी देखा गया था।

जलवायु परिवर्तन से भारत समेत दुनिया भर की एक अरब से अधिक गायों को गर्मी का प्रकोप झेलना होगा



भोपाल। अधिक उत्सर्जन बना रहा तो कई उष्णकटिबंधीय देशों में पशु पालन कठिन हो जाएगा, लेकिन तेजी से उत्सर्जन में कटौती और मवेशी की संख्या को सीमित करने से इस समस्या को 50 से 84 फीसदी तक कम किया जा सकता है। आईओपी पब्लिशिंग के जर्नल एनवायरनमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित नए शोध के अनुसार, अगर कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है और पर्यावरण संरक्षण कम होता है, तो दुनिया भर में एक अरब से अधिक गायें सदी के अंत तक गर्मी से होने वाले तनाव का सामना करेंगी।

इसका मतलब यह होगा कि मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका, भूमध्यरेखीय अफ्रीका और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पशुओं को घातक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। शोध में यह भी पाया गया कि तेजी से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ मवेशी उत्पादन को मौजूदा स्तर के करीब रखने से एशिया में इन प्रभावों को कम से कम 50 फीसदी, दक्षिण अमेरिका में 63 फीसदी और अफ्रीका में 84 फीसदी तक कम किया जा सकता है। अत्यधिक गर्मी मवेशियों को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है, खासकर जब यह अधिक नमी के साथ मिलती है। यह प्रजनन क्षमता को कम करती है, बछड़ों के विकास को बाधित करता है और इसके कारण मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। दूध देने वाली गायों में, यह दूध उत्पादन को भी कम कर देता है। ये सभी पशुपालन खेती की वास्तविकता को प्रभावित करते हैं, पशु कल्याण और कृषि आय को कम करते हैं। मवेशियों पर गर्मी के तनाव के वर्तमान और भविष्य के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए, केप टाउन, क्राजुलु-नटाल और शिकागो विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में आज की गर्मी और नमी की स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि, विभिन्न स्तरों - उत्सर्जन और भूमि उपयोग के प्रकार के आधार पर वे भविष्य में मवेशियों को किस तरह प्रभावित करेंगे। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यदि भविष्य में कार्बन उत्सर्जन बहुत अधिक होता है, तो दुनिया भर में दस में से नौ गायें प्रति वर्ष 30 या अधिक दिन गर्मी के तनाव का अनुभव करेंगी। सदी के अंत तक दस में से तीन से अधिक पूरे साल गर्मी के तनाव का अनुभव करेंगी। जबकि सबसे अधिक प्रभावित देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होंगे। दुनिया के कई अन्य हिस्सों को भी हर साल कई महीनों तक गर्मी की तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको के कुछ इलाकों में, हर साल 180 दिन या उससे अधिक दिनों तक गर्मी सताएगी। बढ़ता तापमान और नमी किसानों को इन नई स्थितियों के अनुकूल होने के लिए मजबूर करेगी, उदाहरण के लिए, जानवरों के लिए वेंटिलेशन या यहां तक कि एयर कंडीशनिंग प्रदान करना या गर्मी-अनुकूलित मवेशी नस्लों को अपनाना। लेकिन ये उपाय भविष्य में तापमान वृद्धि के साथ और अधिक महंगे हो जाएंगे और सभी स्थानों पर यह संभव नहीं होंगे। जिसका अर्थ है कि उन स्थानों पर पशुपालन अब आसान नहीं रह जाएगा जहां यह वर्तमान में एक प्रमुख व्यवसाय है, उदाहरण के लिए भारत, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और उत्तर-पूर्वी अर्जेंटीना, और सहेलियन और पूर्वी अफ्रीकी देशों में। कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने और मौजूदा स्तरों के भीतर पशुधन उत्पादन को बनाए रखने से गर्मी के तनाव के संपर्क में आने वाले मवेशियों की संख्या में काफी कमी आएगी, खासकर एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका सहित कुछ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में। उत्सर्जन कम करने से समशीतोष्ण क्षेत्रों में मवेशियों को आधे से अधिक वर्ष तक गर्मी के तनाव का सामना करने से भी बचाया जा सकेगा। शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि आज के फैसले आने वाले दशकों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उदाहरण के लिए, अमेज़न और मध्य अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में पशुधन के लिए उष्णकटिबंधीय जंगलों

को काटने से न केवल उन क्षेत्रों में मवेशियों की संख्या में वृद्धि होगी जो पहले से ही सबसे अधिक गर्मी के तनाव का सामना कर रहे हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन भी बढ़ोतरी होगी, जिससे पशुपालन बेहद मुश्किल हो जाएगा। आहार में बीफ की मात्रा कम करने और अधिक पौधे-आधारित उत्पाद खाने से पशु उत्पादों की उपभोक्ता मांग कम हो जाएगी। इससे जानवरों को गर्मी के तनाव से खतरा कम होगा, साथ ही वन संरक्षण और खराब भूमि की बहाली के अवसर भी मिलेंगे जो तापमान वृद्धि को सीमित करने में मदद कर सकते हैं। शोधकर्ता ने कहा, हमारे अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मवेशी तेजी से तापमान के संपर्क में आ रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, विकास और उत्पादन को कम कर रहा है और दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ती मौतों का कारण बन रहा है। जिन्हें वर्तमान में प्रमुख मवेशी-कृषि क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम यहां केवल गर्मी के तनाव को देख रहे हैं और पानी की उपलब्धता में बदलाव पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, इसका मतलब यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में पशुपालन कठिन होता जाएगा। शोधकर्ता ने बताया कि, ऐसे सरल समाधान हैं जो मवेशियों पर पड़ने वाले गर्मी के तनाव को कम कर सकते हैं, साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी कम कर सकते हैं और इसलिए समग्र रूप से जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। मौजूदा किसान अपने मवेशियों पर गर्मी के तनाव की मात्रा को कम करने के लिए रणनीतियों को प्राथमिकता देना शुरू कर सकते हैं। अनुभव, समाधानों का चयन करना जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें लागू करने में कितना समय लगता है, वे मवेशियों को गर्मी से निपटने में कितनी मदद कर सकते हैं। वे इस पर भी विचार कर सकते हैं कि क्या कोई अलग है मवेशियों की नस्ल, या विभिन्न पशुओं की प्रजातियों को उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बेहतर ढंग से अनुकूलित किया जा सकता है। शोधकर्ता ने कहा, हमने जलवायु परिवर्तन से मनुष्यों पर पड़ने वाले घातक प्रभावों को देखा है, जिससे लू का प्रकोप तेज हो रहा है, लेकिन जिन जानवरों के उत्पादों हम उपभोग करते हैं, वे भी गर्मी के भयंकर खतरे में हैं। हमें खतरे को सीमित करने के लिए अभी से कार्रवाई करने की जरूरत है। उष्णकटिबंधीय जंगलों को काटकर या जलाकर मवेशी उत्पादन का विस्तार करना टिकाऊ नहीं है, इससे जलवायु परिवर्तन में बढ़ोतरी होती है और सैकड़ों लाखों मवेशियों पर बुरा असर पड़ जाएगा, जो साल भर खतरनाक गर्मी के तनाव का सामना करेंगे। गर्मी के तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए पशुधन कृषि प्रणालियों का अनुकूलन आवश्यक है। आहार में पशु उत्पादों की मात्रा कम करने से भविष्य में पशुपालन के विस्तार को सीमित करने में मदद मिल सकती है। जंगलों की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के अवसर पैदा हो सकते हैं जो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने में मदद कर सकते हैं।

एयर क्वालिटी ट्रेकर- दिल्ली-मुंबई को पीछे छोड़ धनबाद-उल्हासनगर सहित छह शहरों में दमघोंटू हुई हवा, 110 शहरों में संतोषजनक रहा स्तर

नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 226 में से 25 शहरों में हवा बेहतर रही, वहीं 17 अक्टूबर को यह संख्या 35 दर्ज की गई थी। 110 शहरों की श्रेणी %संतोषजनक% रही जबकि 85 शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम रही। वहीं अकोला (215), धनबाद (224), जलगांव (225), नवी मुंबई (211), रायचंगपुर (215) और उल्हासनगर (270) में प्रदूषण का स्तर दमघोंटू रहा।

यदि दिल्ली की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता %मध्यम% श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 129 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में इंडेक्स 140, गाजियाबाद में 107, गुरुग्राम में 149, नोएडा में 129, ग्रेटर नोएडा में 156 पर पहुंच गया है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 199 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के %मध्यम% स्तर को दर्शाता है। जबकि लखनऊ में यह इंडेक्स 62, चेन्नई में 109, चंडीगढ़ में 78, हैदराबाद में 86, जयपुर में 93 और पटना में 115 दर्ज किया गया। वहीं आगरा, अलवर, अनंतपुर, अरियालूर, आरा, औरंगाबाद (बिहार), बही, बागपत, बारां, बाड़मेर, बेगूसराय, बेलगाम, बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु, भिलाई, भीलवाड़ा, भिवानी, बीदर, बिलासपुर, चंडीगढ़, छपरा, चिकबलपुर, चित्तूर, चुरू, कुड्डलोर, देहरादून, देवास, धारुहेड़ा, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, गांधीनगर, गंगटोक, गया, गोरखपुर, गुवाहाटी, हापुड़, हसन, हावेरी, हिसार, होसुर, हुबली, हैदराबाद, इंफाल, जबलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालंधर, जलना, झालावाड़, जींद, कैथल, कलबुर्गी, कांचीपुरम, कन्नूर, कानपुर, करौली, करनाल, काशीपुर, खन्ना, खुर्जा, कोच्चि, कोल्हापुर, कुंजपुरा, कुरुक्षेत्र, लातूर, लखनऊ, मदिकेरी, महाड, मंडी

गोबिंदगढ़, मांडीखेड़ा, मेरठ, मिलुपारा, मुरादाबाद, मुंगेर, मैसूर, नलबाड़ी, ऊटी, पाली, पंचकुला, परभनी, पटियाला, प्रयागराज, रायपुर, रामानगर, रामनाथपुरम, रोहतक, राउरकेला, सागर, सहरसा, सलेम, सांगली, सवाई माधोपुर, शिलांग, शिवमोगा, सीकर, सिलीगुड़ी, सिंगरौली, सिरोही, सिरसा, श्रीगंगानगर, तालचेर, टेंसा, त्रिशूर, तिरुपति, तुमिडीह, उदयपुर, उडुपी, विजयवाड़ा, वृंदावन, यमुनानगर आदि 100 शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही, जहां सूचकांक 51 से 100 के बीच दर्ज किया गया।

देश में वायु प्रदूषण के स्तर और वायु गुणवत्ता की स्थिति को आप इस सूचकांक से समझ सकते हैं जिसके अनुसार यदि हवा साफ है तो उसे इंडेक्स में 0 से 50 के बीच दर्शाया जाता है। इसके बाद वायु गुणवत्ता के संतोषजनक होने की स्थिति तब होती है जब सूचकांक 51 से 100 के बीच होती है। इसी तरह 101-200 का मतलब है कि वायु प्रदूषण का स्तर माध्यम श्रेणी का है, जबकि 201 से 300 की बीच की स्थिति वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को दर्शाती है।

वहीं यदि सूचकांक 301 से 400 के बीच दर्ज किया जाता है जैसा दिल्ली में अक्सर होता है तो वायु गुणवत्ता को बेहद खराब की श्रेणी में रखा जाता है। यह वो स्थिति है जब वायु प्रदूषण का यह स्तर स्वास्थ्य को गंभीर और लम्बे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद 401 से 500 की कटेगरी आती है जिसमें वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर बन जाती है। ऐसी स्थिति होने पर वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि वो स्वस्थ इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए तो यह जानलेवा हो सकती है।

पानी को बुरी तरह से प्रदूषित कर रहे हैं प्लास्टिक से बने कृत्रिम टर्फ के खेल के मैदान-अध्ययन

मुंबई। कृत्रिम टर्फ पानी में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि जलीय वातावरण में तैरते हुए पाए जाने वाले पांच मिमी से अधिक लंबाई वाले 15 फीसदी प्लास्टिक के लिए जिम्मेदार है। अध्ययन के मुताबिक, यूरोपीय संघ में हर साल लगभग 1,200 से 1,400 कृत्रिम टर्फ से बने खेल के मैदान स्थापित किए जाते हैं। ये मैदान सिंथेटिक फाइबर, मुख्य रूप से प्लास्टिक से बने होते हैं, जो प्राकृतिक घास की तरह दिखती है।

हाल ही में, कृत्रिम टर्फ को लेकर, बार्सिलोना विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान संकाय के समुद्री भूविज्ञान में शोध टीम ने एक अध्ययन किया। अध्ययन में पहली बार, कैटलन तट और गुआडलक्विरी नदी के सतही पानी से एकत्र किए गए नमूनों में कृत्रिम टर्फ फाइबर की भारी मात्रा पाई गई। शोध के निष्कर्षों से पता चलता है कि कृत्रिम टर्फ पानी में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि जलीय वातावरण में तैरते हुए पाए जाने वाले पांच मिमी से अधिक लंबाई वाले 15 फीसदी प्लास्टिक के लिए जिम्मेदार है। प्रमुख शोधकर्ता विलियम पी. डी हान ने बताया कि, कृत्रिम टर्फ फाइबर जो हमें मिले हैं वे मुख्य रूप से पॉलीइथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन के हैं, जो कृत्रिम टर्फ के वर्तमान वैश्विक उत्पादन रूझानों से मेल खाते हैं और आमतौर पर जलीय वातावरण में तैरते हुए पाए जाते हैं। हमने उन्हें ज्यादातर बार्सिलोना जैसे बड़े शहरों से सटे निकटवर्ती क्षेत्रों में पाया। शोधकर्ताओं के अनुसार, अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कृत्रिम टर्फ फाइबर जलीय पर्यावरण में प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा स्रोत है और यह भविष्य के अध्ययनों में उनकी पहचान करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रदान करता है। ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले उनके वितरण और उनके विशिष्ट प्रभावों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। एनवायर्नमेंटल पोल्यूशन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कैटलन तट और ग्वाडलक्विरी नदी की समुद्री सतह से एकत्र किए गए नमूनों का विश्लेषण किया है। शोधकर्ताओं ने बार्सिलोना के तट से एकत्र किए गए 217 और ग्वाडलक्विरी नदी से 200 पानी के नमूनों का विश्लेषण किया और समुद्र से एकत्र किए गए अधिकांश नमूनों 62 प्रतिशत में कृत्रिम टर्फ फाइबर पाया गया, जबकि नदी से प्राप्त नमूनों में यह 37 प्रतिशत था। नदी के पानी की तुलना में सतह पर मात्रा औसतन 50 गुना अधिक थी। बार्सिलोना के निकट सतही जल में प्रति वर्ग किलोमीटर तक 2,00,000 फाइबर पाए गए और ग्वाडलक्विरी नदी में प्रति दिन 20,000 फाइबर तक प्रवाहित हुए। शोधकर्ताओं के अनुसार, ये अंतर नदियों में प्लास्टिक की कमी के कारण हो सकते हैं, विशेष रूप से मौसमी बारिश के दौरान और तटीय क्षेत्र में समुद्र की सतह पर कृत्रिम टर्फ फाइबर के लंबे समय तक जमा होने के कारण, जहां प्लास्टिक वर्षों तक बना रहता है। दशकों पहले खुले समुद्र तक पहुंचने से पहले यहां यह बरकरार रहा। शोधकर्ता इस बात पर भी जोर देते हैं कि, हालांकि परिणाम विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में हासिल किए गए थे, इस बात के भी आसार हैं कि, अन्य शहर भी कृत्रिम टर्फ फाइबर में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन पर्यावरण में जारी मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि प्रकार, उपयोग और कृत्रिम टर्फ क्षेत्रों या सतहों की आयु, स्थापित कुल सतह क्षेत्र और लागू रोकथाम के उपाय। शोध से पता चला पर्यावरणीय प्रभाव, कई और बहुत गंभीर हैं, क्योंकि वे पर्यावरण पर इस सामग्री के प्रभाव को और बढ़ाते हैं। अध्ययन में इस बात का भी पता लगाया गया कि, शहरी जैव विविधता को कम करने, अपवाह को कम करने, अधिक गर्मी और बड़ी मात्रा में हानिकारक रासायनिक यौगिकों से युक्त जो इसे स्थायित्व प्रदान करते हैं, कृत्रिम टर्फ सतहें प्लास्टिक के टुकड़े जलीय वातावरण में छोड़ती हैं। शोधकर्ता का कहना है कि ये प्लास्टिक जलीय जानवरों द्वारा निगल लिए जाते हैं और इनके आंतों के रस्ते में रुकावट और अन्य बड़ी समस्याओं के अलावा विकास और प्रजनन दर में कमी के लिए जिम्मेदार हैं। शोधकर्ता ने कहा, अगर हम महासागरों के प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस पर कार्रवाई करना आवश्यक है सभी स्तरों पर, सार्वजनिक क्षेत्रों, जैसे कि स्कूल के मैदान या खेल के मैदान और निजी, जैसे संगीत समारोह, जिम, निजी उद्यान या छतों पर इन हरी प्लास्टिक सतहों की स्थापना पर पुनर्विचार करना जरूरी है।